

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 20/24

जीसीएमएस संख्या 2024/103

वर्ष 2024

बउनवानी:-दिनेश चन्द पुत्र श्री रामूसिंह मीना निवासी ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील खण्डार
बनाम

1. सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.8.2023 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टिकल रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थित:-श्री राधेश्याम वैष्णव

श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक)

वकील अपीलान्त

पैरोकार रसद

-:निर्णय :-

दिनांक:- 20.8.2025

यह अपील अपीलान्त द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 28.8.2023 जिसके द्वारा अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात विपक्षी की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्त एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रुयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य होने योग्य हैं। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील खण्डार की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 1369/2001 है एवं प्रार्थी को रसद सामग्री वितरण हेतु पोस मशीन संख्या 19871 आवंटित की गयी है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के ग्राम पंचायत दौलतपुरा के उपभोक्ताओं को नियमित रूप से रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.6.2016, 19.7.2016 एवं 5.8.2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात दिनांक 24.3.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा अपने आधार कार्ड एस अंगूठे का बायोमेट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री दी जाती है एवं रसद सामग्री प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के मोबाईल नम्बर पर आता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ताओ को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर आ जाने के कारण राशनकार्ड मे रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दी जाये। उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर आ जाने बाबत आदेश पारित किये गये है। यह तर्क भी दिया कि पूर्व में जिला रसद अधिकारी द्वारा

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(अपील रसद संख्या 20/2024 उनवानी दिनेश चन्द बनाम जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर)

द्वारा अपने आदेश दिनांक 8.8.2019 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया गया जिसको प्रार्थी द्वारा जरिये याचिका माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा सुनवायी की जाकर अपने आदेश दिनांक 30.7.2020 द्वारा निलंबन आदेश दिनांक 8.8.2019 की क्रियान्वति को स्थगित कर दिया गया जिसकी पालना में जिला रसद अधिकारी अपने आदेश दिनांक 5.8.2020 द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा राजनैतिक रंजिशवश प्रार्थी की झूठी शिकायत की गयी जिसके आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक श्री रिपुदमन सिंह द्वारा दिनांक 17.01.2023 को प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान की जाँच की गयी जिसकी रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.01.2023 को जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को प्रस्तुत की गयी जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 6.2.2023 द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः निलंबित किया जाकर दिनांक 10.2.2023 को कारण बताओं नोटिस जारी किया जिसमें ज्यादातर तकनीकी प्रकृति के आरोप अंकित किये गये जिसका उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 17.8.2023 को जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। किन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के जवाब को कन्सीडर किये बिना एवं प्रार्थी को सुनवायी को अवसर दिये बिना ही अपने आदेश दिनांक 28.8.2023 से प्रार्थी का प्राधिकार पत्र अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 30.7.2020 प्रभावी था। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जाँच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवायी गयी ओर ना ही दस्तावेज आदि उपलब्ध करवाये,लेकिन जाँच दल द्वारा बिना किसी उचित माप तोल के ही अन्दाजन रसद सामग्री की गणना की जाकर प्रार्थी के उपर रसद सामग्री के दुरुपयोग का आरोप प्रमाणित माना गया है जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई भी स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी द्वारा रसद सामग्री का गबन किया हो। विधि में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में आरोपो को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एसबी किमीनल 759/2025 की पालना में प्रार्थी के गोदाम में पीओएस मशीन संख्या 19871 के स्टॉक में दर्ज 65897.04 किलोग्राम गेहूँ को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.6.2025 को अटैचमेंट डीलर श्री गोरधन गर्ग ग्राम पंचायत अल्लापुर की सुपुदर्गी में दिया जा चुका है जिसको प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अटैचमेंट डीलर की दुकान में शिफ्ट करवा दिये गये है। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना किसी स्पष्ट साक्ष्य के प्रार्थी के उपर रसद सामग्री के दुरुपयोग का आरोप प्रमाणित माना जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया जो विधिसम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 28.8.2023 में प्रार्थी के उपर प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,7,8,9,10,11,17 सी एवं 18 का उल्लंघन माना जाकर प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है किन्तु यह नहीं अंकित नहीं किया कि प्रार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लंघन किया है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी का एक मात्र रोजगार यह दुकान है तथा प्रार्थी के उपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है। प्रार्थी के उपर गबन एवं कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है उसके बावजूद भी प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी ठोस कारण के निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 25.3.1994 में तकनीकी अनियमितताओं बाबत डीलरो के चिरुद्ध प्रकरण दर्ज नहीं करने के दिशा निर्देश पारित किये गये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

.....(2).....

०१
(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



(अपील रसद संख्या 20/2024 उनवानी दिनेश चन्द बनाम जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर)

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त दिनेश चन्द मीना उ.मू.दुकानदार की वितरण संबंधी शिकायत पेश होने पर शिकायत की जांच क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक श्री रिपुदमन सिंह से करवाये जाने के आदेश दिये जाने पर श्री रिपुदमन सिंह द्वारा दिनांक 17.01.2023 को जांच कर दिनांक 20.01.2023 को जांच रिपोर्ट जिला रसद कार्यालय मे प्रस्तुत की गयी। जांच के दौराने वितरण संबंधी एवं स्टॉक संबंधी पायी गयी अनियमितताओ के कारण उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र आदेश क्रमांक/अभियोग/2023/149 दिनांक 6.2.2023 को निलंबित किया जाकर पायी गयी अनियमितताओ के क्रम में कारण अनियमितताएं पायी गयी। 1. वरवक्त निरीक्षण दुकान बन्द मिली। 2. दुकान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड व अन्य सूचनाएं दुकान पर अंकित नहीं करना पाया गया। 3. मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया गया किन्तु मोबाईल रिसेवर नहीं किया गया। 4. ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि अधिकृत राशन की दुकान पर राशन का वितरण नहीं किया जाता है। महिने मे सिर्फ 1-2 दिन ही राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। शेष दिनों मे दुकान बंद रखी जाती है। गांव के एक बंद पडे खण्डर स्कूल में राशन वितरण किया जाता है एवं ज्यादातर ग्रामवासी राशन से वंचित रह जाते है। 5. ग्राम वासियो द्वारा बताया गया कि दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से अंगूठे लगवा लिये जाते है और बाद में राशन वितरण नहीं किया जाता है। 6. ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि राशन डीलर अधिकतर समय शराब के नशे मे रहता है एवं उपभोक्ताओं को डराता-धमकाता है। महिलाओ के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। 7. दुकानदार को दुकान पर बुलाने उप उपस्थित हुआ एवं दुकान पर उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन करवाया गया। दुकान मे खाद्यान्न सामग्री शुन्य पायी गयी जबकि पोस मशीन मे एनएफएसए गेंहूँ 36940.04 किलोग्राम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 28957 किलोग्राम एवं अन्य सहायता का 4473 किलोग्राम गेंहूँ दर्ज है जिसका दुकानदार द्वारा गबन कर लिया गया। 8. मौके पर स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये। 9. मौके पर दुकान लाईसेंस, किरायानामा, दुकान नक्शा, उपलब्ध नहीं करवाया गया। उक्त नोटिस का जवाब अपीलान्त द्वारा दिनांक 17.8.2023 को प्रस्तुत कर आरोप संख्या 1 को छोडकर सभी आरोप को गलत बताया गया है। यह तर्क भी दिया कि निलंबन के पश्चात दुकानदार ने माह फरवरी 2023 की मात्रा 5692.260 नियमित किलोग्राम गेंहूँ का पीओएस मशीन मे स्टॉक रिसिव नहीं किया गया एवं अटैचमेंट डीलर को केवल पीओएस मशीन संख्या 19871 सुपुर्द की गयी। खाद्यान्न सामग्री आज दिनांक 28.8.2023 तक नहीं दी गयी है। अटैचमेंट डीलर से लिया गया बयान पूछताछ क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.8.2023 को प्रस्तुत किया गया। यह तर्क भी दिया कि दुकानदार द्वारा एनएफएसए गेंहूँ 36940.04 किलोग्राम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 28957 किलोग्राम एवं अन्य सहायता का 4473 किलोग्राम गेंहूँ अन्न सहायता चना 172 किलोग्राम एवं चीनी 337 किलोग्राम का प्रथम दृष्टया दुरुपयोग किया जाना पाया गया जो पीओएस मशीन मे वक्त जांच दर्ज था इसके पश्चात प्रबंधक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम सवाईमाधोपुर द्वारा आपूर्ति किया गया माह फरवरी 2023 के पेटे मात्र 5692.260 किलोग्राम गेंहूँ नियमित योजना का पीओएस मशीन में स्टॉक रिसिव नहीं किया गया जिसका भी दुरुपयोग दुकानदार द्वारा कर लिया गया। श्री अरविन्द भरावन, अस्थायी अटैचमेंट दुकानदार को केवल

.....(3).....


02
(जाना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(अपील रसद संख्या 20/2024 उनवानी दिनेश चन्द बनाम जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर)
पीओएस मशीन संख्या 9871 सुपुर्द की गयी। खाद्यान्न सामग्री दिनांक 28.8.2023 तक नही दी गयी है। इस प्रकार अपीलान्त द्वारा कुल 76062.30 किलोग्राम गेहूँ, 172 किलोग्राम चना एवं 337 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग किया जाना साबित होने पर अपीलान्त का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,7,8,9, 10,11,17(सी) एवं 18 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने के कारण दौराने जाँच पायी गयी अनियमितताओं पर अपीलान्त डीलर को युक्तियुक्त सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु अपीलान्त द्वारा उस पर लगाये गये आरोप बैबुनियान्त होने बाबत कोई संतोष जनक जवाब एवं साक्ष्य सबूत पेश नही किया तथा दुरुपयोग किये गये गेहूँ, चना एवं चीनी अस्थायी डीलर को नही दिया गया। अतः राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए अपीलान्त डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्त खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्त एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्त डीलर श्री दिनेश चन्द मीना, उ०मू०दुकानदार ग्राम दोलतपुरा तहसील खण्डार द्वारा किया गया कथन कि जाँच दल द्वारा रसद सामग्री की नाप तोल नही की गयी है एवं अन्दाज से ही नाप तोल कर प्रकरण बनाया है किन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्त द्वारा पेश नही किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.8.2019 को प्रस्तुत जवाब के आधार पर अपीलान्त को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने की पुष्टि हो जाती है। अपीलान्त डीलर पर रसद सामग्री 76062.30 किलोग्राम गेहूँ के गबन बाबत लगाये गये आरोप में से अपीलान्त द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एसबी किमीनल 759/2025 की पालना में गबन की गयी राशन सामग्री में से 65897.04 किलोग्राम गेहूँ अटैचमेंट डीलर श्री गोरधन गर्ग को दिनांक 27.6.2025 को सम्भला दिये गया है। अर्थात् स्वयं अपीलान्त द्वारा भी उक्तानुसार राशन सामग्री का गबन किया जाना माननीय न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है। अपीलान्त द्वारा अटैचमेंट डीलर को राशन सामग्री सम्भला देने से उसपर लगाये गये आरोप कम नही हो जाते हैं बल्कि लगाये गये आरोपों में से 65897.04 किलोग्राम गेहूँ के गबन की बखूबी पुष्टि हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा की कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर